





इकाई- 5

Unit - 5

आर्थिक क्षेत्र में  
सरकार की भूमिका

Economic Presence  
of the Government

अध्याय- 7 जनसुविधाएं  
Public Facilities

**CLASS**

**VIIIth**

**(Polity)**

**NCERT**

**Based**



By : Karan Sir

इकाई - 5

अध्याय- 7

जनसुविधाएं

इकाई पाँच

Unit Five

Public Facilities

जनसुविधाएँ



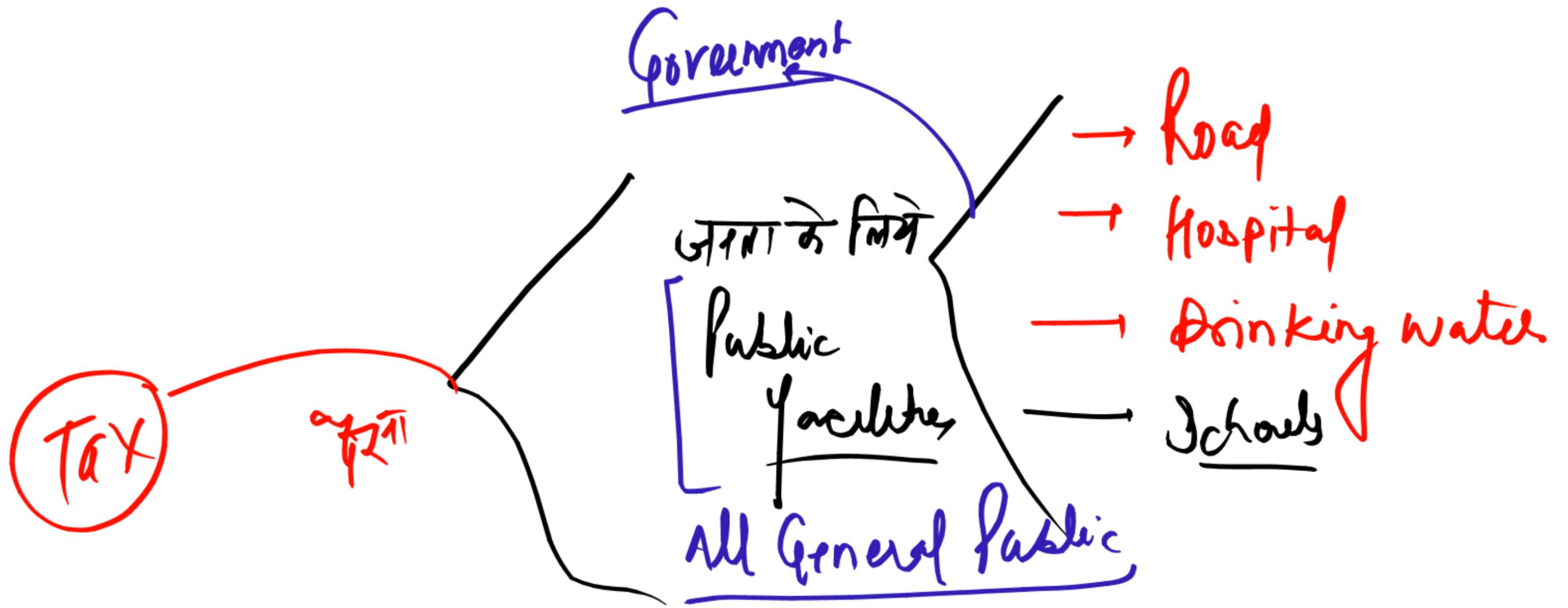


अमू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफ़र कर रहे हैं। शहर के अलग-अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं...

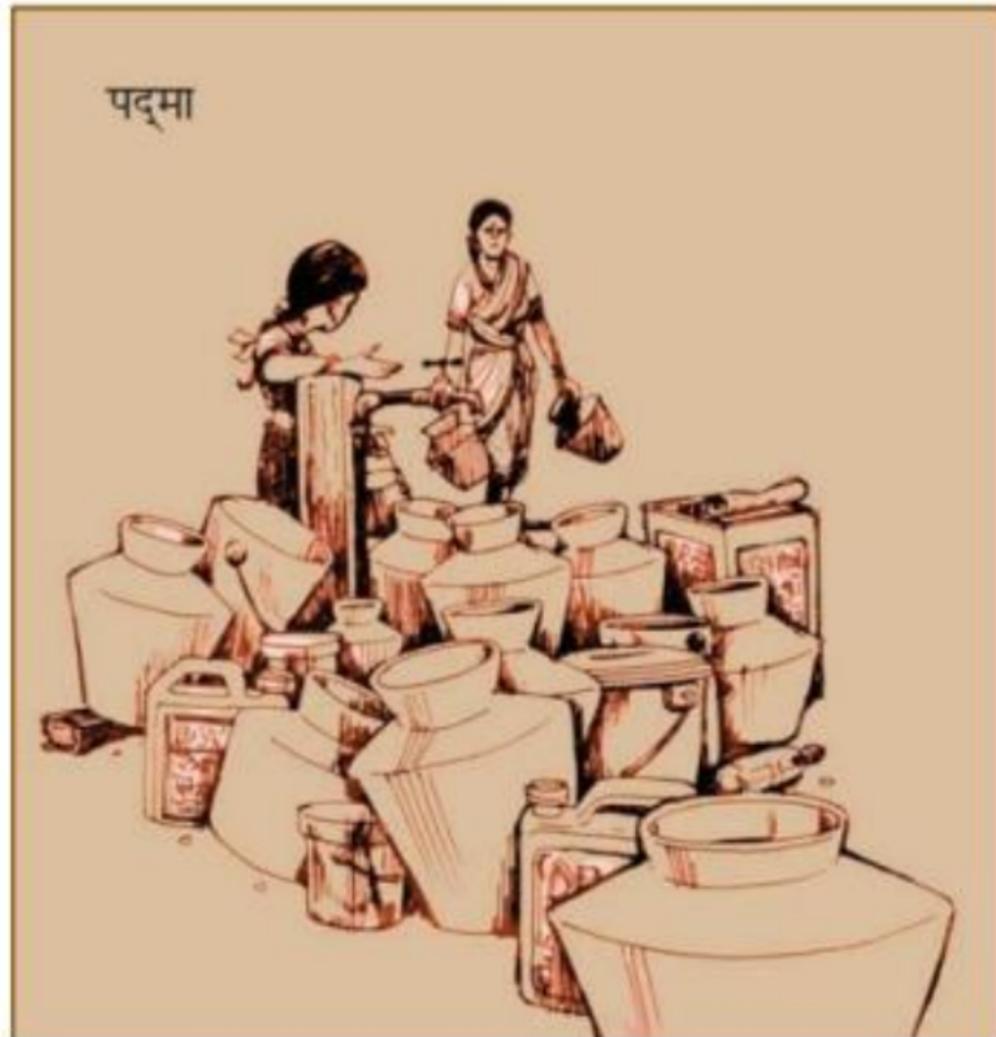
Amu and Kumar are travelling through Chennai in a bus. As they go round the city, they observe the water facilities available in different parts of Chennai...

### ANNA NAGAR अन्नानगर





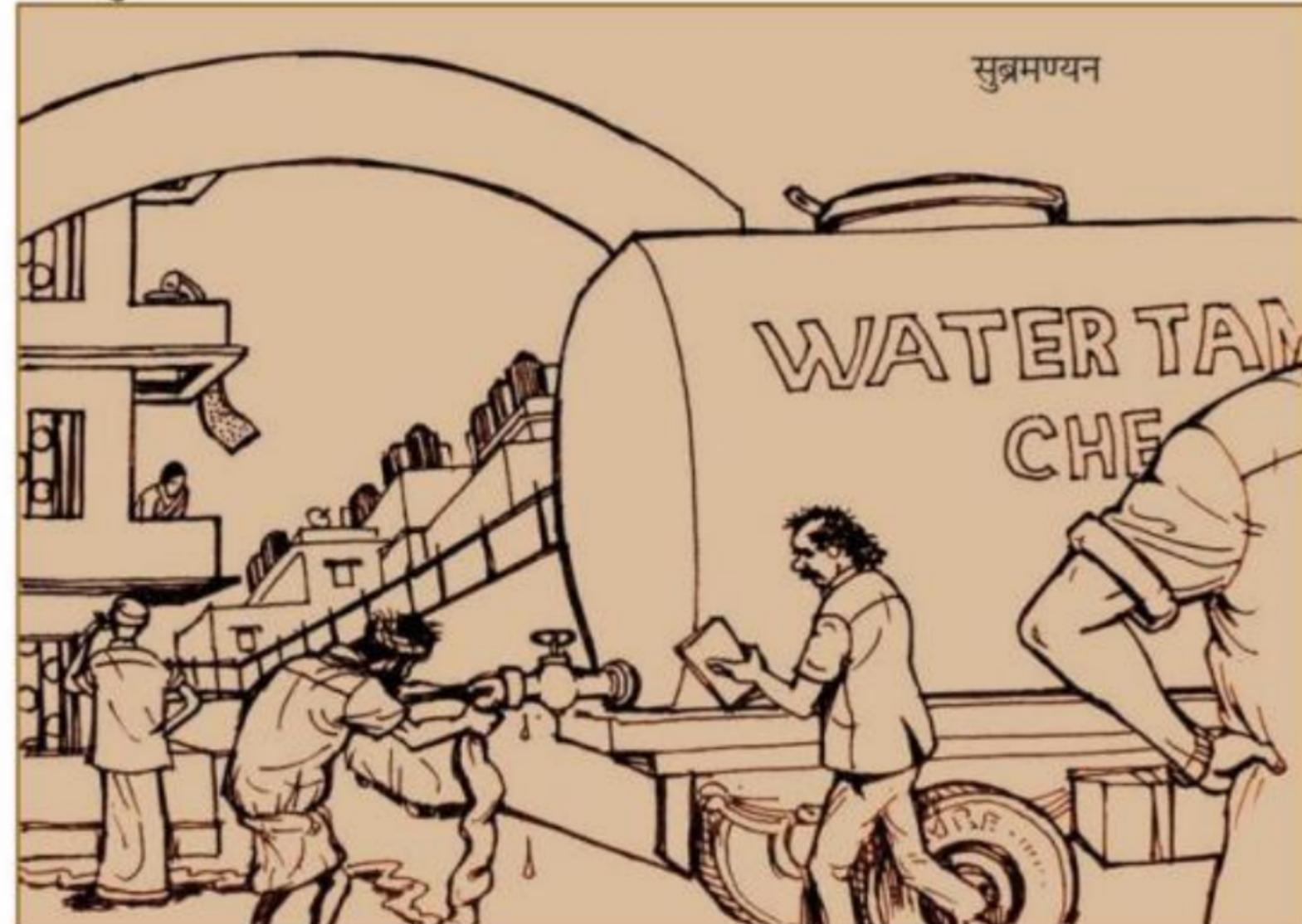
SAIDAPET सैदापेट



मडीपाक्कम MADIPAKKAM



मैलापुर MYLAPORE



## चेन्नई के लोग और पानी

श्री रामगोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे-भरे बाग-बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री रामगोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फ़ौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतज़ाम हो जाता है।

## Water and the People of Chennai

Senior government officials like Mr Ramagopal live in Anna Nagar, Chennai. This area looks lush and green with lawns maintained by a generous spraying of water. Bungalows here have tap water for major part of the day. On days when the water supply is inadequate, Mr Ramagopal speaks to a senior official whom he knows in the municipal water board and a water tanker is easily arranged for his house.

शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगरपालिका दो दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं। लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ़-सफ़ाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यन टैंकों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500-600 रुपए खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ़ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जलशोधन उपकरण लगवाए हुए हैं।

Like most areas of the city, Subramanian's apartments in Mylapore suffers from water shortage. This area gets municipal water once in two days. A private borewell meets some of the residents' water needs. Borewell water is, however, brackish so the residents use it in their toilets and for washing. For other uses, water is purchased from tankers. Subramanian spends upto Rs 500-600 per month on buying water from the tankers. For drinking water, residents have installed water purification systems in their homes.

Now

मडीपाक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे चार दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाज़ार से पानी की बोतलें खरीदता है।

Siva lives on rent on the first floor of a house in Madipakkam and gets water once in four days. Shortage of water is one major reason why Siva can't bring his family to Chennai. For drinking, Siva buys bottled water.

पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपए माहवार है। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है और न ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज़ 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियाँ भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतज़ार करना पड़ता है।

Padma works as a domestic help in Saidapet and lives in the nearby slum. She pays a rent of Rs 650 for the hutment, which has neither a bathroom nor a tap connection. For 30 such hutments there is a common tap at one corner, in which water comes from a borewell for 20 minutes twice daily. A family gets to fill a maximum of three buckets within this time. The same water is used for washing and drinking. In summer, the flow becomes a trickle, so that one family gets water only at the cost of another. People have to wait long hours for water tankers.

1. आपने ऊपर उल्लिखित चार स्थितियों को देखा है। अब बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है।
2. उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुनें।
3. आपकी राय में सुब्रमण्यन और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है।
4. अपने इलाके में जलापूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें।
5. देश के ज्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूँद-बूँद क्यों आने लगता है? पता लगाइए।

कक्षा में चर्चा के लिए-

क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है? क्या आप बता सकते हैं कि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? दो कारण बताएँ।

1. You have seen the four situations illustrated above. Based on these, what impression do you get of the water situation in Chennai?
2. Pick out the various sources of water for household use from the description alongside.
3. What, in your view, is similar, and what is different in Subramanian's and Padma's experiences.
4. Write a paragraph describing the water supply situation in your area.
5. Why does water flow in a trickle in summer in most places in India? Find out.

Discuss: Is there a general shortage of water for everyone in Chennai? Can you think of two reasons why different people get varying amounts of water?



## जीवन के अधिकार के रूप में पानी (21)

जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ़ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेन्सिया, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुँह में चले जाते हैं। उनमें से ज्यादातर पाँच साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है।

Clean  
drinking

## Water as Part of the Fundamental Right to Life

Water is essential for life and for good health. Not only is it necessary for us to be able to meet our daily needs but safe drinking water can prevent many water-related diseases. India has one of the largest number of cases of diseases such as diarrhoea, dysentery, cholera. Over 1,600 Indians, most of them children below the age of five, reportedly die everyday because of water-related diseases. These deaths can be prevented if people have access to safe drinking water.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर-गरीब, हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुँच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए।

The Constitution of India recognises the right to water as being a part of the Right to Life under Article 21. This means that it is the right of every person, whether rich or poor, to have sufficient amounts of water to fulfil his/her daily needs at a price that he/she can afford. In other words, there should be universal access to water.

21 = high to life

Drinking water - पीने का पानी

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात का फिर दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गाँव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि सह गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज़ 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएँ।

There have been several court cases in which both the High Courts and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a Fundamental Right. In 2007, the Andhra Pradesh High Court restated this while hearing a case based on a letter written by a villager of Mahbubnagar district on the contamination of drinking water. The villager's complaint was that a textile company was discharging poisonous chemicals into a stream near his village, contaminating ground water, which was the source for irrigation and drinking water. The judges directed the Mahbubnagar district collector to supply 25 litres of water to each person in the village.

“...जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुँच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए।”

संयुक्त राष्ट्र 2002

“... right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use”

United Nations (2002)



## जनसुविधाएँ

पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएँ भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने ~~स्वास्थ्य~~ और ~~स्वच्छता~~ इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। इन्हें जनसुविधाएँ के नाम से जाना जाता है।

## Public Facilities

Like water, there are other essential facilities that need to be provided for everyone. Last year you read about two other such facilities, healthcare and sanitation. Similarly, there are things like electricity, public transport, schools and colleges that are also necessary. These are known as **public facilities**.



भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है।

The Indian Constitution guarantees the Right to Education for all children between the ages of 6-14 years. Equity in the schooling facilities available to all children is an important aspect of this Right. However, activists and scholars working on education have documented the fact that schooling in India continues to be highly unequal.

21(A)

किसी जनसुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गाँव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है : किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंपसेट चला सकते हैं, लोग बिजली से चलने वाली छोटी-माटी वर्कशॉप खोल सकते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ने-लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गाँव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है।

The important characteristic of a public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people. For instance, a school in the village will enable many children to get educated. Similarly, the supply of electricity to an area can be useful for many people: farmers can run pumpsets to irrigate their fields, people can open small workshops that run on electricity, students will find it easier to study and most people in the village will benefit in some way or the other.

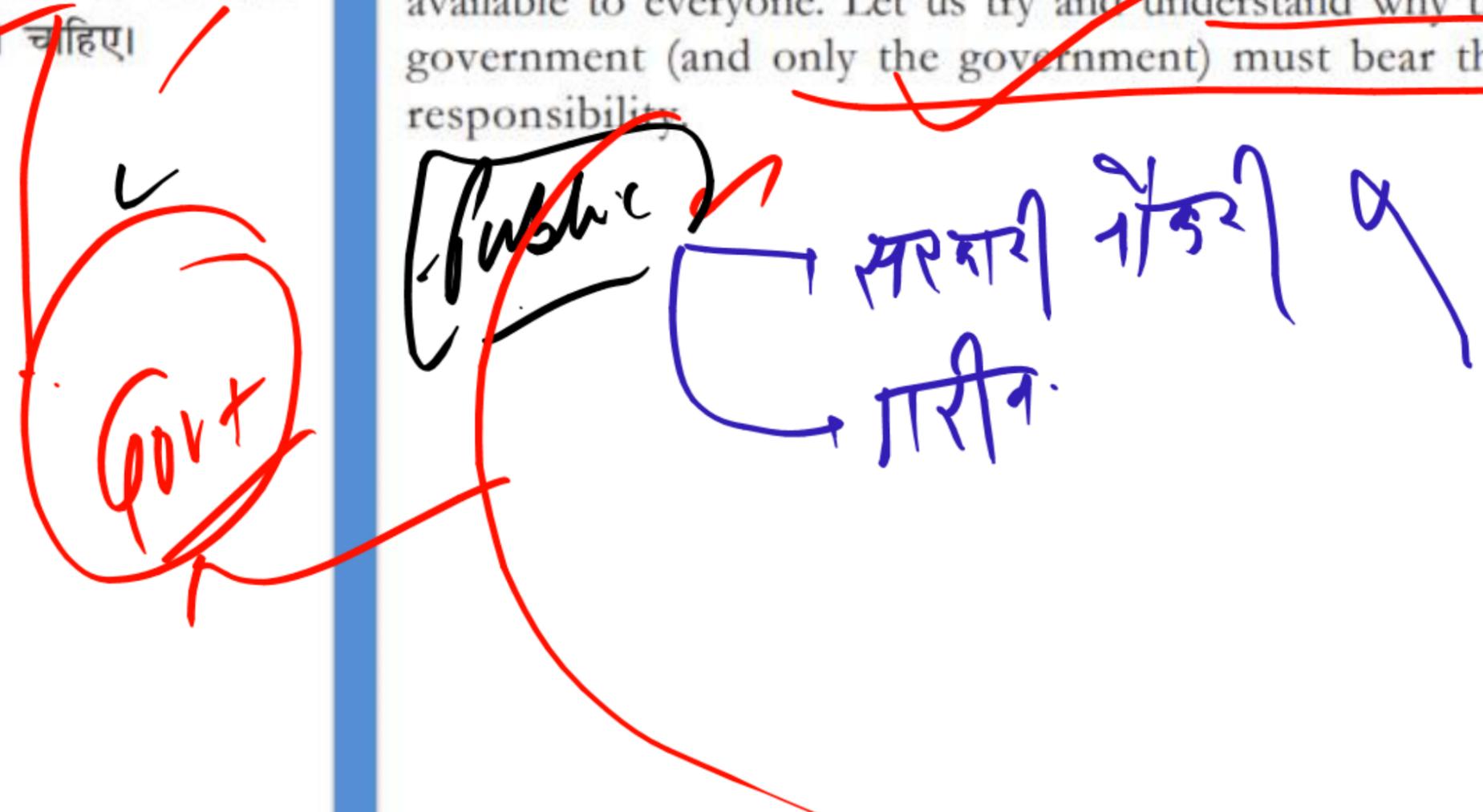
Qum

## सरकार की भूमिका

चूँकि जनसुविधाएँ इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जनसुविधाएँ मुहैया कराए। आइए, इस बात को समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार (और केवल सरकार) को ही क्यों उठानी चाहिए।

## The Government's Role

Given that public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing these to the people. This 'someone' is the government. One of the most important functions of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. Let us try and understand why the government (and only the government) must bear this responsibility.







The government needs to play an active role in providing adequate access to proper health facilities for the entire population. This includes the eradication of preventable diseases like polio as shown in the above photograph.

*Pen*

सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे बच्चे को पोलियो की खुराक दी जा रही है।

लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जनसुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियाँ जनसुविधाएँ तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएँ पाएँगे, यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएँगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएँगे।

But, for other public facilities such as schools and hospitals, private companies may well be interested. We have many of these, particularly in large cities. Similarly, if you are living in a city, you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles. In such cases, private companies provide public facilities but at a price that only some people can afford. Hence, this facility is not available to all at an affordable rate. If we go by the rule that people will get as much as they can pay for then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life.

✓  
Khan

यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जनसुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जनसुविधाएँ मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजिमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए।

Public facilities  
 Govt  
 P.M.  
 Govt

Clearly, this is not a desirable option. Public facilities relate to people's basic needs. Any modern society requires that these facilities are provided so that people's basic needs are met. The Right to Life that the Constitution guarantees is for all persons living in this country. The responsibility to provide public facilities, therefore, must be that of the government.

Public facilities →

Government →

PM

Govt

Govt

सरकार को जनसुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है?

आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े-नुकसान का ब्यारा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है।

बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुँचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें।

Where does the government

Every year you must have been being presented in the Parliament. It shows the government's income and expenses the government has made in the past year and how much it has spent in that year.

In the budget, the government also announces the ways in which it plans to raise money. The main source of revenue for the government is from the people, and the government has to collect these taxes and use them, for instance, to supply water, to pump water, in pumping water, carrying water down pipes for distribution, to remove impurities, and finally, to collect the money. It meets these expenses partly by the money it collects and partly by the money it sets so that most people can afford a certain amount of water for daily

किमा - किमा जय  
Income - Expends.

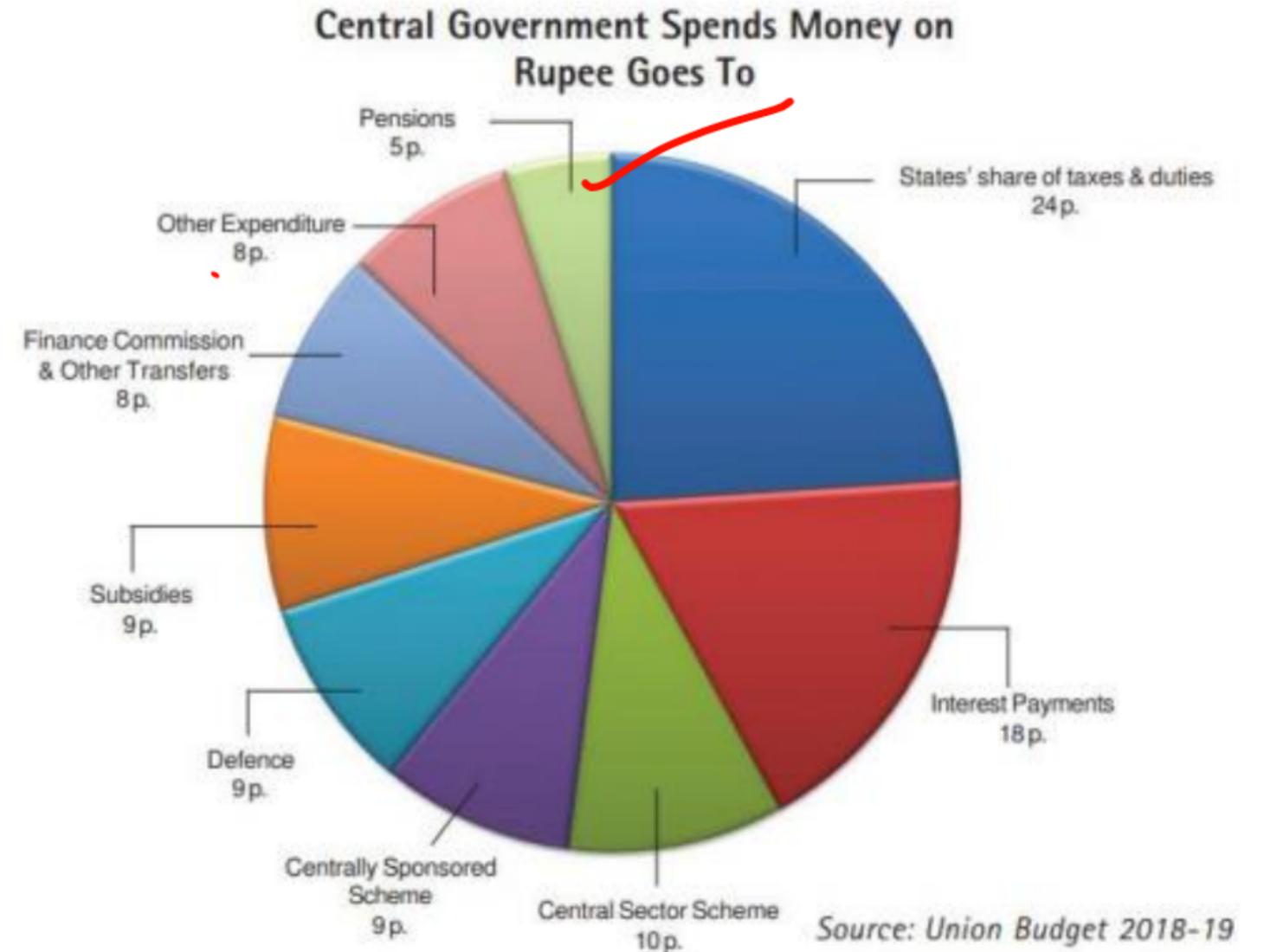
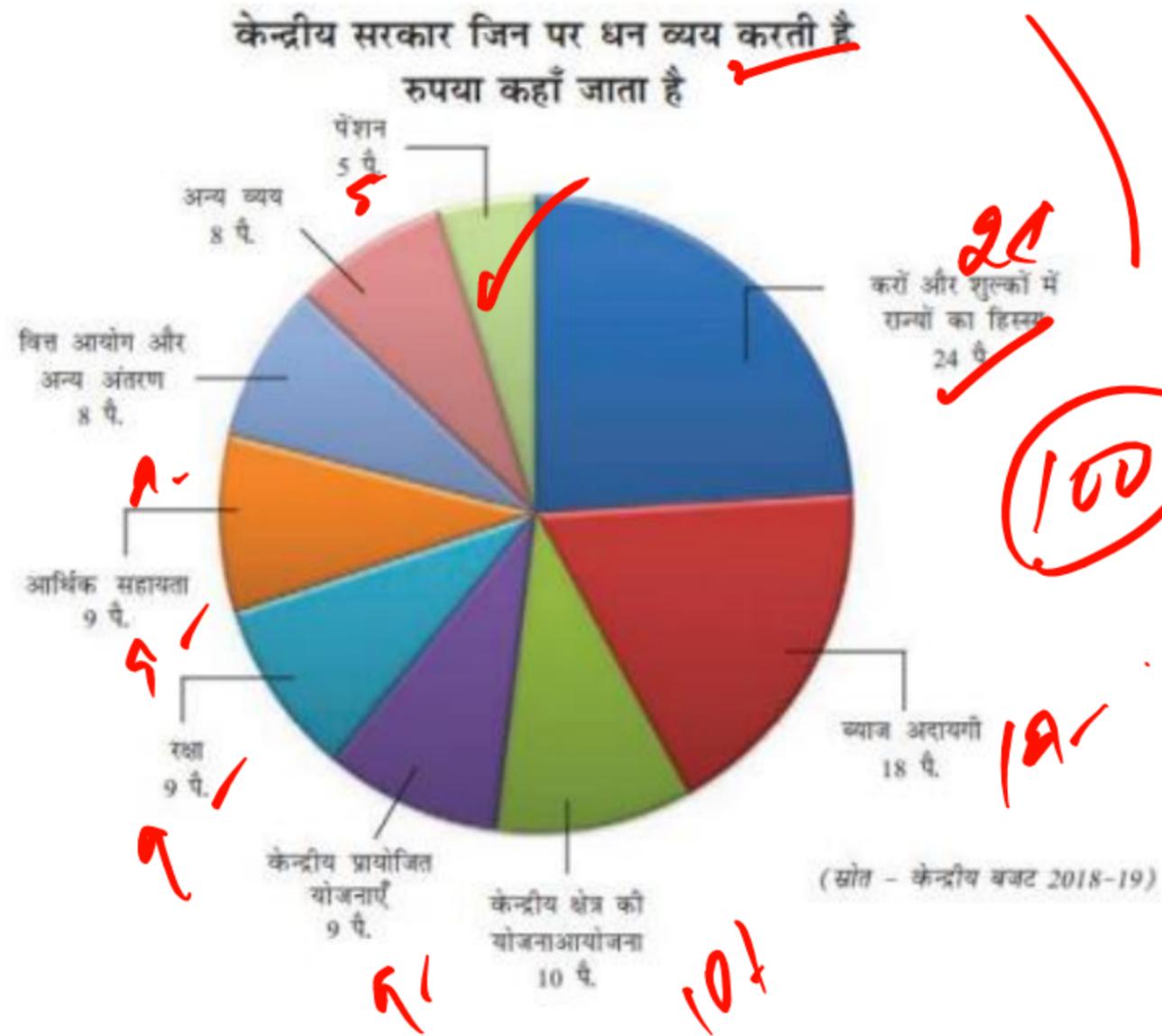
100

110

थरुप

Q

वधि -  
वर्ष



मरुत वजए - जिता - १.

अमू- देखा तुमने, सैदापेट की सड़कें कितनी ऊबड़-खाबड़ थीं? सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी। पता नहीं रात में वहाँ क्या हालत होती होगी!



कुमार- किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी!

अमू- झुग्गी बस्तियाँ ऐसी क्यों होती हैं? क्या वहाँ जनसुविधाएँ नहीं होनी चाहिए?

कुमार- मेरे खयाल में जनसुविधाएँ उन लोगों के लिए होती हैं जो बस्तियों में ठीक-ठाक घरों में रहते हैं। वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं।

अमू- सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह केवल 'ठीक-ठाक' बस्तियों को ही नहीं, बल्कि सभी को जनसुविधाएँ मुहैया कराए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो कुछ अधिकार हैं।

कुमार (गुस्से में)- पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी!

अमू- चाहे जो हो, उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में जिंदगी कैसी होगी?

कुमार- अरे...!

अमू- हमारे संविधान में बहुत सारी जनसुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना न हो ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके।

आप किसकी राय से सहमत हैं?

As Amu and Kumar ride around Chennai...



Amu: Did you notice that the roads in Saidapet were so bumpy and without streetlights? I wonder what the place is like at night.

Kumar: What better can you expect in a slum!

Amu: Why should slums be like that? Shouldn't they have public facilities?

Kumar: I think public facilities are for all those who live in proper houses in colonies. They are the people who pay taxes.

Amu: Why do you say that! Slum dwellers are also citizens and they have rights too.

Kumar: Arrey! The government will go bankrupt this way!

Amu: Well, it has to find a way. Can you imagine what it would be like to live in a slum without proper roads, water, electricity?

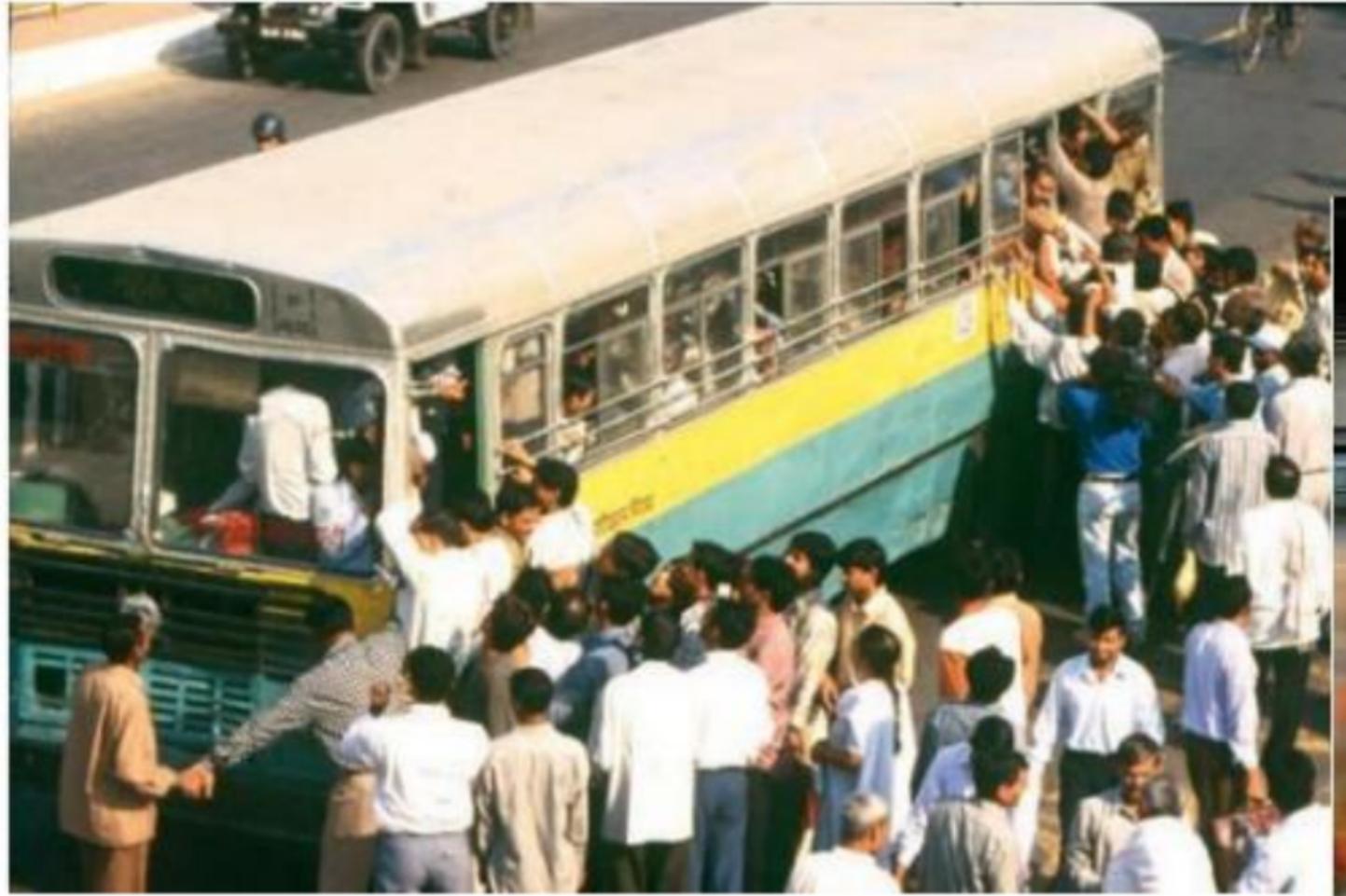
Kumar: Err....

Amu: Our Constitution recognises many of the public facilities as being a part of the Right to Life. The government must see that these rights are protected so that everyone can lead a decent life.

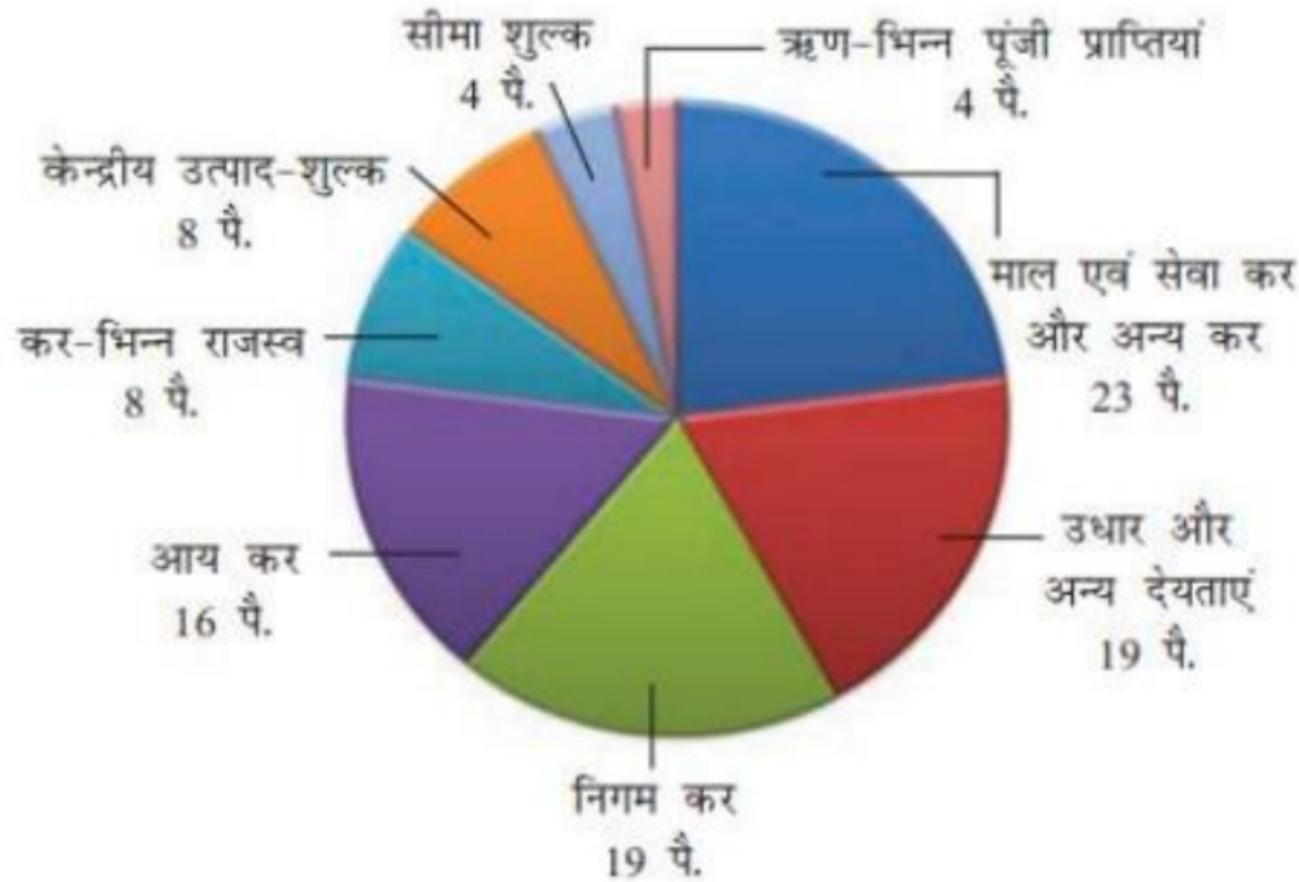
**Whose point of view do you agree with?**

1. जनसुविधाएँ क्या होती हैं? जनसुविधाएँ मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए?
2. सरकार कुछ जनसुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम दो निजी कंपनियों के हाथ में है। लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुँचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ें।  
आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनसुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के ज़रिए भी करवा सकती है?
3. अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएँ कि आपके इलाके में नगरपालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है?
4. किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय/फैक्टरी चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएँ कि लोग किस-किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाएँ और चर्चा करें।

1. What are public facilities? Why should the government be responsible for providing public facilities?
2. The government can get private companies to deliver some of the public facilities. For instance, contracts for building roads are given to private contractors. Distribution of electricity in Delhi is done by two private companies. However, the government must keep a close watch on these and ensure that they fulfil their commitment to reach these facilities to all people and at affordable prices.  
  
Why do you think the government must assume the overall responsibility for public facilities even when it gets private companies to do part of the job?
3. Look at your water bill and find out what the minimum rate is for municipal water in your area. Does the rate increase as the use of water increases? Why do you think the government charges a higher rate for greater use of water?
4. Find out the various kinds of taxes people pay to the government by talking to a salaried person, a person running his or her own factory/business and a shopkeeper. Share your findings in the classroom with your teacher.

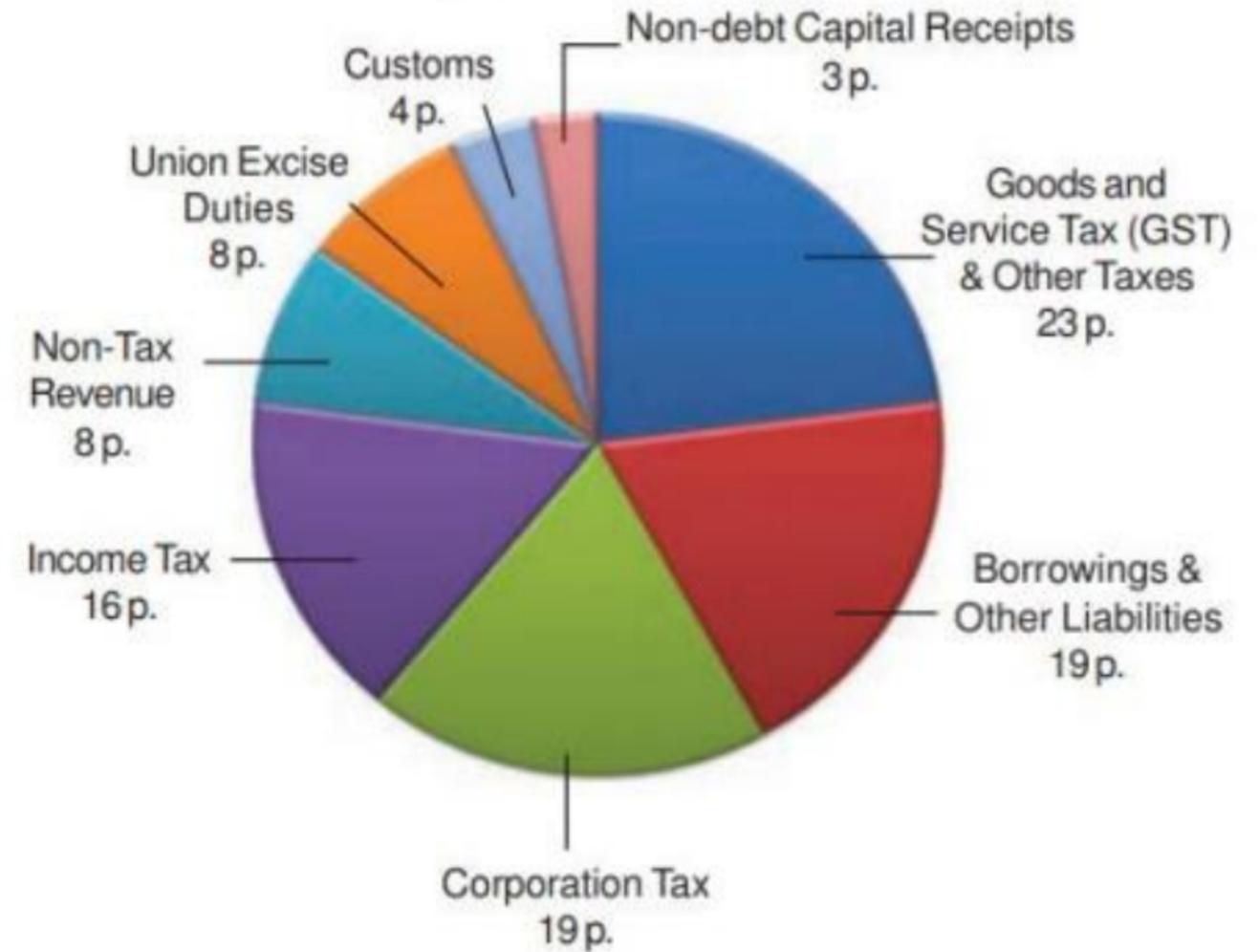


केन्द्रीय सरकार के कर राजस्व  
रुपया कहाँ आता है



(स्रोत - केन्द्रीय बजट 2018-19)

Tax Revenue of Central Government  
Rupee Comes From



Source: Union Budget 2018-19

कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। ज्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तेज़ शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है।

Buses are the most important forms of public transport over short distances. It is the main link to the workplace for majority of the working people. With rapid urbanisation, the public bus system even in the major cities has not been able to keep up with the demand.

Car

Person

Traffic

Pollution

Heat wave

इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मैट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मैट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्च की ज़रूरत न पड़ती और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है? आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूँढ़ा जा सकता है?

As an alternative, the government has planned ambitious metro rail projects for Delhi and other metropolitan cities. Rs 11,000 crore was spent from the government budget for the construction of the first segment of the metro-rail in Delhi using the latest technology. People have pointed out that this massive expenditure could have been avoided if only a fraction of this amount was spent on upgrading the public bus system. Would you agree? What do you think could be the solution for other regions of India?

*Public Transport*

चेन्नई में पानी की आपूर्ति : क्या सबको पानी मिल रहा है?

Water Supply to Chennai: Is it Available to All?

ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों, दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ कुआँ, हैंडपंप, तालाब और कभी-कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में हैं। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज्यादा अभाव है।

In rural areas, water is needed both for human use and for use by the cattle. The sources of water are wells, handpumps, ponds and sometimes overhead tanks. Much of these are privately owned. Compared to the urban areas, there is an even greater shortage of public water supply in rural areas.



इसमें कोई शक नहीं कि जनसुविधाएँ सभी को मुहैया होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जनसुविधा बहुत मायने रखती है।

While there is no doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facilities. In the rest of this chapter, we will read about the provision of water, which as we have seen, is a public facility of great importance.

जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगरपालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है। कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है।

Water supply in Chennai, as we saw at the beginning of the chapter, is marked by shortages. Municipal supply meets only about half the needs of the people of the city, on an average. There are areas which get water more regularly than others. Those areas that are close to the storage points get more water whereas colonies further away receive less water.

जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूँढ लेते हैं। वे बोरवेल खोद कर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतलबंद पानी खरीद का अपना काम चला लेते हैं।

The burden of shortfalls in water supply falls mostly on the poor. The middle class, when faced with water shortages, are able to cope through a variety of private means such as digging borewells, buying water from tankers and using bottled water for drinking.

व्यापक रूप

गरीबों

पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को 'सुरक्षित' पेयजल तक पहुँच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह सपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतलबंद पानी और जलशोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ़ पानी मिल जाता है। परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाज़ा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति 'पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने' के लक्ष्य से बहुत दूर है।

1.15  
PC 5

Apart from the availability of water, access to 'safe' drinking water is also available to some and this depends on what one can afford. Once again, the wealthy have more choices, thanks to the booming market in bottled water and water purifiers. People who can afford it have safe drinking water, whereas the poor are again left out. In reality, therefore, it seems that it is only people with money who have the right to water – a far cry from the goal of universal access to 'sufficient and safe' water.

Harshit

### किसानों से पानी छीनना

742

पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफ़े के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियाँ शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद कर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मामंदूर, पालुर, कारुनगिज़ी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गाँवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है, बल्कि गाँवों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीज़ा यह है कि इन सारे कस्बों और गाँवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है।

742 पर्व  
7

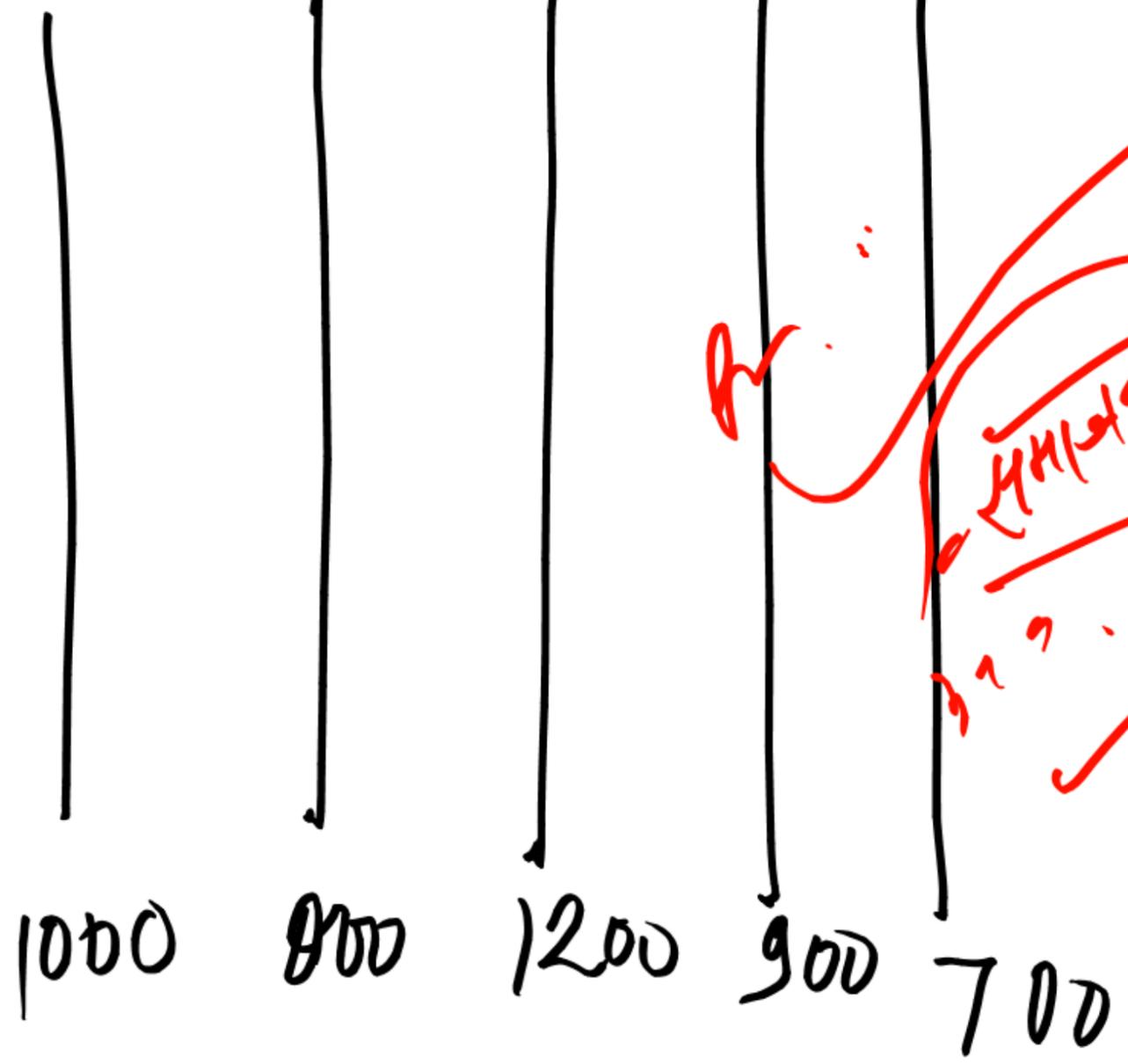
### Taking water from farmers

The shortage of water has opened up opportunities for private companies in a big way. Many private companies are providing water to cities by buying it from places around the city. In Chennai, water is taken from nearby towns like Mamandur, Palur, Karungizhi and from villages to the north of the city using a fleet of over 13,000 water tankers. Every month the water dealers pay farmers an advance for the rights to exploit water sources on their land. This is water taken away not just from agriculture but also from the drinking water supplies of the villagers. Ground water levels have dropped drastically in all these towns and villages as a result.

(A)

4600 ₹

6170 ₹



सही है  
क्या



## विकल्पों की तलाश

चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगरपालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियाँ अपने मुनाफ़े के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर-बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है। लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोज़ाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी (एक बाल्टी) भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ़ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोज़ाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर (80 बाल्टी) तक पानी मिलता है।

## In Search of Alternatives

The situation in Chennai is not unique. A similar scenario of shortages and acute crisis during the summer months is common to other cities of India. The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit. Also common are the great inequalities in water use. The supply of water per person in an urban area in India should be about 135 litres per day (about seven buckets) – a standard set by the Urban Water Commission. Whereas people in slums have to make do with less than 20 litres a day per person (one bucket), people living in luxury hotels may consume as much as 1,600 litres (80 buckets) of water per day.

चर्चा करें : अगर सरकार जलापूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींच ले तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि यह सही कदम होगा?

Discuss: Do you think this would be a right step? What do you think would happen if the government withdraws from the task of supplying water?

नगरपालिका के ज़रिए जलापूर्ति में कमी को अकसर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूँकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियाँ ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं।

A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water departments are running at a loss, we should allow private companies to take over the task of water supply. According to them, private companies can perform better.

इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए-

1. दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं।
2. दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुँच चुकी है (नीचे बॉक्स देखें)।
3. जहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफ़ा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीन कर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी।

Consider the following facts:

1. Throughout the world, water supply is a function of the government. There are very few instances of private water supply.
2. There are areas in the world where public water supply has achieved universal access. (see Box below)
3. In a few cases, where the responsibility for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water, making it unaffordable for many. Cities saw huge protests, with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hands.

### पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति

पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फ़ायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएँ तय करने में वोट के ज़रिए फ़ैसला करती है।

### Public Water Supply in Porto Alegre

Porto Alegre is a city in Brazil. Though there are many poor people in this city, what is remarkable is that it has a far lower number of infant deaths as compared to most other cities of the world. The city's water department has achieved universal access to safe water and this is the main reason behind the lower number of infant deaths. The average price of water is kept low, and the poor are charged half the basic rate. Whatever profit the department makes is used to improve the water supply. The working of the water department is transparent and people can have a direct say in deciding which projects the department should take up. Through a process of public meetings, people hear what the managers have to say and also vote on their priorities.

4. भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं। लेकिन ये उदाहरण कम हैं और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफ़ा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं ताकि भूमिगत जलस्तर में सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएँ ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है। इसलिए इन टैंकरों को 'अनुबंधित' कहा जाता है।

4. Within India, there are cases of success in government water departments, though these are few in number and limited to certain areas of their work. The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. In Hyderabad, a report shows that the department has increased coverage and improved performance in revenue collection. In Chennai, the department has taken several initiatives for harvesting rain water to increase the level of groundwater. It has also used the services of private companies for transporting and distributing water but the government water supply department decides the rate for water tankers and gives them permission to operate. Hence they are called 'on contract'.

ऊपर के भाग में आए मुख्य विचारों पर चर्चा करें। जलापूर्ति में सुधार के लिए आपकी राय में क्या किया जा सकता है?

क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है?

Discuss the main ideas in the above section. What do you think can be done to improve water supply?

Do you think it is also important to conserve resources like water and electricity, and to use more public transport?



मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर-दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूँढ़ने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन-सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते।

Mumbai's suburban railway is well-functioning public transport system. It is the densest route in the world, attending to 65 lakh passengers daily. Extending over a distance of 300 kilometers, these local trains allow people living far away from Mumbai to find work in the city. Note that the high cost of housing in cities makes it impossible for an average worker to live in the city.

## स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार



“ ‘हमारे लिए पाखाने/शौचालय!’ उन्होंने हैरानी से कहा।

‘हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं।’

‘लैट्रीन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है।’ ”

‘अछूतों’ की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य,  
राजकोट स्वच्छता समिति, 1896.

पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87 प्रतिशत परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएँ (घर के भीतर शौचालय) 53 प्रतिशत परिवारों में ही उपलब्ध हैं। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज्यादा कमज़ोर दिखाई देती है।

### Extending Sanitation Facilities



“Latrines for us!’ they exclaimed in astonishment.  
‘We go and perform our functions out in the open.’  
Latrines are for you big people.”

Mahatma Gandhi recounting untouchables’ grievances,  
Rajkot Sanitation Committee, 1896

Besides safe drinking water, sanitation is a must in prevention of water-borne diseases. However, the sanitation coverage in India is even lower than that of water. Official figures for 2011 show that 87 percent of the households in India have access to drinking water and about 53 percent have access to sanitation (toilet facilities within the premises of residence). Once again, it is the poor both in the rural and urban areas who lack access to sanitation.

गैर-सरकारी संगठन 'सुलभ इंटरनेशनल' पिछले लगभग पाँच दशक से निम्न-जाति, निम्न-आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 8,500 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और 15,00,000 से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं जिससे दो करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं।

सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगरपालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए ज़मीन और पैसा मुहैया कराते हैं जबकि रख-रखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है (शहरों में शौचालयों के इस्तेमाल पर ₹2 शुल्क लिया जाता है)।

अगली बार जब आप सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है खुद यह जानना चाहें कि ये शौचालय कैसे होते हैं!

क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? कैसे?

आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे औरतों और लड़कियों पर ज्यादा गहरा असर पड़ेगा?



Besides safe drinking water, sanitation is a must in prevention of water-borne diseases. However, the sanitation coverage in India is even lower than that of water. Official figures for 2011 show that 87 percent of the households in India have access to drinking water and about 53 percent have access to sanitation (toilet facilities within the premises of residence). Once again, it is the poor both in the rural and urban areas who lack access to sanitation.

Sulabh, a non-government organisation, has been working for nearly five decades to address the problems of sanitation facing low-caste, low-income people in India. It has constructed more than 8,500 community toilet blocks and 1.5 million household toilets, giving access to sanitation to 20 million people. The majority of the users of Sulabh facilities are from the poor working class.

Sulabh enters into contracts with municipalities or other local authorities to construct toilet blocks with government funds. Local authorities provide land and funds for setting up the services, whereas maintenance costs are sometimes financed through user charges (for example, ₹2 is charged for use of the latrines in the cities).

Next time you see a Sulabh toilet, you might want to find out yourself how it functions!

Do you think that lack of access to proper sanitation facilities affects peoples' lives? How?

Why do you think that this would impact women and girls more acutely?





2001 की जनगणना के अनुसार 44 प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली पहुँच चुकी है। इसका मतलब यह है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अँधेरे में हैं।



The Census of India, 2001 puts rural household electrification at 44 per cent, leaving around 78 million households still in the dark.

## निष्कर्ष

जनसुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जनसुविधाएँ मुहैया कराए।

Govt - जिम्मेदार!

## Conclusion

Public facilities relate to our basic needs and the Indian Constitution recognises the right to water, health, education etc as being a part of the Right to Life. Thus one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone.

NCERT

जिम्मेदार!

Chunary

लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएँ समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए।

But, progress on this front has been far from satisfactory. There is a shortage in supply and there are inequalities in distribution. Compared to the metros and large cities, towns and villages are under-provided. Compared to wealthy localities, the poorer localities are under-serviced. Handing over these facilities to private companies may not be the answer. Any solution needs to take account of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities which should be provided to her/him in an equitable manner.

## अभ्यास

1. आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं?
2. क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें।
3. किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है?
4. ऐसा क्यों है कि ज्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही हैं?
5. क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जनसुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें।

## Exercises

1. Why do you think there are so few cases of private water supply in the world?
2. Do you think water in Chennai is available to and affordable by all? Discuss.
3. How is the sale of water by farmers to water dealers in Chennai affecting the local people? Do you think local people can object to such exploitation of ground water? Can the government do anything in this regard?
4. Why are most of the private hospitals and private schools located in major cities and not in towns or rural areas?
5. Do you think the distribution of public facilities in our country is adequate and fair? Give an example of your own to explain.

6. अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जनसुविधाओं को देखें। क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? इस तालिका को भरें।

	क्या यह उपलब्ध है?	उसमें कैसे सुधार लाया जाए?
पानी		
बिजली		
सड़क		
सार्वजनिक परिवहन		

6. Take some of the public facilities in your area, such as water, electricity, etc. Is there scope to improve these? What in your opinion should be done? Complete the table.

	Is it available?	How can it be improved?
Water		
Electricity		
Roads		
Public Transport		

7. क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जनसुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएँ।
  8. जनगणना के साथ-साथ कुछ जनसुविधाओं के बारे में भी आँकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है।
  9. हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान – स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान – बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्त्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? चर्चा कीजिए।
- 
7. Are the above public facilities shared equally by all the people in your area? Elaborate.
  8. Data on some of the public facilities are collected as part of the Census. Discuss with your teacher when and how the Census is conducted.
  9. Private educational institutions – schools, colleges, universities, technical and vocational training institutes are coming up in our country in a big way. On the other hand, educational institutes run by the government are becoming relatively less important. What do you think would be the impact of this? Discuss.



**स्वच्छता-** मानव मल-मूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा। इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफ़ाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है।

**कंपनी-** कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है।

**सार्वभौमिक पहुँच-** जब हर व्यक्ति को कोई चीज़ पूरी तरह हासिल हो जाती है और वह उसका खर्च उठा सकता है तो इसे सार्वभौमिक पहुँच कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर में नल में पानी आ रहा हो तो परिवार को पानी तक पहुँच मिल जाती है और अगर उसकी कीमत कम हो या वह मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है।

**मूलभूत सुविधाएँ-** भोजन, पानी, आवास, साफ़-सफ़ाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं।



**Sanitation:** Provision of facilities for the safe disposal of human urine and faeces. This is done by construction of toilets and pipes to carry the sewerage and treatment of waste water. This is necessary so as to avoid contamination.

**Company:** A company is a form of business set up by people or by the government. Those that are promoted and owned by individuals or groups are called private companies. For example, Tata Steel is a private company whereas Indian Oil is a company run by the government.

**Universal access:** Universal access is achieved when everyone has physical access to a good and can also afford it. For instance, a tap connection at home will allow physical access to water, and if the price of water is low or is provided free, everyone will be able to afford it.

**Basic needs:** Primary requirements of food, water, shelter, sanitation, healthcare and education necessary for survival.

धन्यवाद